

एक और बेतुका बयान

विवादित बयान देने के लिए चर्चित उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक संगीत सोम ने तोजामहल का जिक्र करते हुए जैसी बयानबाजी की, वह बेतुकी भी है और गैरजरूरी भी। हैरत की बात यह है कि उन्होंने तोजामहल को वस्तु बताने का काम तब किया, जब कुछ ही समय पहले उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की पुस्तिका में उसका नाम न शामिल किए जाने पर राज्य सरकार को सफाई देने के लिए विवश होना पड़ा था। इससे बड़ी दिव्यना और क्या हो सकती है कि जब मुजफ्फरपुर प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी विरोधी को विधायक के मसले पर चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं, तब उनके ही दल के विधायक इतिहास खोलते हुए व्यर्थ का विवाद पैदा कर रहे हैं। ऐसे बूढ़े बयान भाजपा के

यह दिव्यना ही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी विरोधी दलों को विकास के मसले पर चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं, तब उनके दल के विधायक इतिहास खंगालते हुए व्यर्थ विवाद पैदा कर रहे हैं।

की भरपाई हो जाती है, तो यह सही नहीं। हर बेतुका बयान किसी न किसी तरह पर पाटी की छत्रि को नुकसान पहुंचता है। कई बार अपने नेताओं के गैरजरूरी बयानों के चलते भाजपा नेतृत्व को ऐसे विमर्श में उलझना पड़ता है जो विकास के उसके एजेंडे से लोगों का ध्यान भटकाता है। यह नितात आश्चर्य है कि भाजपा बेतुके बयान देने वाले अपने नेताओं के प्रति और सख्ती बरते। यह अक्षय की बात है कि तीन साल बाद भी समीत सोम जैसे भाजपा के कई नेता यह समझने से इनकार कर रहे हैं कि मोदी सरकार का एजेंडा विकास है, न कि इतिहास को नर सिरे से लिखना या फिर अतीत की गलतियों को ठीक करना। निःसंदेह यूपी में भी भाजपा को पंचव बहमत इस्लामि नहीं मिला कि लोग यह चार रहे थे कि तोजामहल को अलग नगरिये से देखने का काम किया जाना है। क्या यह भाजपा के एजेंडे में था कि सता में आए तो यह पता लगाएंगे कि तोजामहल किन परिस्थितियों में और कैसे बना? इसी तरह क्या ऐसा कोई बात किया गया था कि इतिहास से कुछ लोगों का नाम निकाला जाएगा? आखिर जो कुछ अरुणो ने हो चुका था फिर बन-भिड़ कुछ, उसमें फेरबदल करने का क्या मतलब? बेहतर हो कि सोम व उनके जैसे अन्य लोग तोजामहल को जैसा है, वैसा ही बना रहने दें। यदि उन्हें दुनियाभर में पहचान रखने वाली इस इमारत में कुछ खास नजर नहीं आता तो यह उसकी सराहना न करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं कि तोजामहल तो गढ़वाले न बनया था। यह पहली बार नहीं जब तोजामहल को लेकर कोई विवाद उठा हो। यह-रखबर ऐसा होता आ रहा है, लेकिन इससे सनभाव की तोकाप्रियता पर कोई अगर नहीं पड़ा। भारी ही तोजामहल मुकत-एक कदम हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक भया इमारत है और दुनिया के सात अजुबों में शामिल है।

बढ़ गई बेटियां

एक समय ऐसा भी था, जब हरियाणा सिंग अनुपात के मामले में सबसे पिछड़ा था। यहां लड़कों की संख्या के अनुपात में लड़कियों की संख्या बाकी राज्यों के मुकाबले बेहद कम हुआ करती थी। और यह आंकड़ा देश के नीति-निर्देशां और महिला संगठनों के लिए चिंता का सबब भी था। एक समय वहाँ पुरुषों पुरुष प प्रधान मानसिकता और इससे जुड़े अन्य कारण लड़कियों की घटती मिलती के लिए जिम्मेदार थे। लड़कियों को तो या तो कोस में ही मार दिया जाता था या पैदा होते ही गला घोट दिया जाता था। वैसे भी देश के संघर्ष युनिव समाज राज्यों मस्तन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में एक समय सिंग अनुपात बेहद स्तर था। लेकिन सरकार के प्रयास और लोगों में जागरूकता बढ़ने के चलते इस गूढ़ समस्या को धमक फिलता दिखने लगा है। खासकर हरियाणा जो कन्या-पुत्र हथकड़ी के लिए बदनाम रहा है, अब समाजीकिय ढंग से बदलाव को देख, सुन और समझ रहा है। केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इससे महत्ववांशी योजना "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का कारगरतम अंतर प्रदेशियों में दिखने लगा है। महज दो साल पहले हरियाणा के ही सीपीएम जिले से इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार की मही साल भी कि लड़कियों की संख्या और उन पर ज्यादातरों के जितने दाम पूर्व में लगे थे, उन्ने निर्दिष्टा हर हाल में जरूरी है। और दो साल के अंदर यह दाम मिता दिखाना पड़ने लगा है। हालांकि इससे कुछ साल पहले तक योगीन विमलता, भूषा हत्या और लड़कियों से भेगाव के मामले में हरियाणा की देश भर में नगरात्मक छवि थी। यह सब कुछ जागरूकता के प्रयास, साक्षरता का स्तर बढ़ाते और बेहतर कानून-व्यवस्था के चलते संभव हो सका है। यह बहुत बड़ी और नजीरी मिलाल है। निःसंदेह हरियाणा सरकार इसके लिए कबाई करी ही हकदार है। जता में अकेले-दुर्गे की समझ बढ़ने से ही आज हरियाणा का सीना गर्व से खड़ा है। पतावा का साक्षर होना इस समय में महत्वपूर्ण है। एक बेटी के पढ़ने से दो परिवार का साक्षर होत है। कह सकते हैं कि आने वाले वर्षों में कुछेक कारण समाजिक आंदोलनों में यह अभियान भी जरूर अपनी मौजूदगी दर्ज करेगा।

टूटि प्याइंट/ आलोक पुराणिक

दियाली सेल कथाएं

एक-शॉनिंग सिर्फ शॉनिंगएक समय की बात है-लंका नामक राज्य में लोग सिर्फ दो ही काम करते थे। एक ईएमआई के लंका जिले से और दूसरा हर तरह की चीज खरीदते थे। परिणाम हुआ कि लंका में बुझाभार कम जिए जाने लगे। छेड़, कर्ज देने को कर्मियोंका पैसा देती थीं लंका में नागरिकों के पास सोना बहुत होता था। नगरपुर फाइनने कोमली सोना लेकर कर्ज देने लगीं-धीमे-धीमे लंकावासियों का संसार गमगुम पड़ने लगा। कर्मियों के पास आ गया। ऐसे में लंका पर आक्रमण हुआ। देवरी-भानुजने न आक्रमण किया। लंका के राजा ने पहिले से छह-तुन सह आक्रमण का जवाब देता। इसके प्रत्युत्तर में पहिले ने कोला-हमरी लाहफ में अब क्या रहे? सिर्फ मोबाइल और शॉनिंग। ऐसे में हम जीतकर भी क्या करें। और हमने के लालूज जहां तक है तो हमारे पास हमने के लिए कुछ बचा ही नहीं है सिर्फ मोबाइल के काबज के तो हम लड़ें ही क्यों। पहिले के ऐसे वन सुनकर लंका का राजा हलाम रह गया। मोबाइल कॉमनिये एक नम कॉमनिये पर सम्यक निगताम लड़ पाये के लिए हद को कोला। छेड़, लंका का राजा हद रह गया। विशा-इस हकती से हम यह विशा मिलती है कि हम फिलहाल की लोका में रहम नहीं खर्च करनी चाहिए और मोबाइल के लिए सोने को गिरी नहीं रखना चाहिए कथा नर-वे-कुम्भर्ण की मॉडलिंगकुम्भर्ण अति ही ताकतवर योद्धा था लंका की सेना में, पर वह युद्ध के क्त सोता पाया गया, अति ही शिथिल अवस्था में। कथा यों है कि कुम्भर्ण ने एक गध कर्णों से मॉडलिंग काटेंदत लिया था, जिसमें लिखा था कि वह महीने-महीने गध पर सोता पड़ा रहेगा। इतिहास में टैलाइनन बोलोग-गधे ऐसे कि उन्ने का दिल ही ना करे। युद्ध के समय कुम्भर्ण से बहुत निरस्त किया गया कि मर्या, उठत ली। लंका की इज्जत का स्वागत है। पर कुम्भर्ण महीने सोने के काटेंदत के चलते युद्ध करने में सक्षम ही ना बचा। मजदुरों ने जो किया, उन्ना कारण परिणाम लंका की हार के सामने आया। विशा-ज्यादा मॉडलिंग के खबर में न पड़ना चाहिए, परफार्मेंस खराब हो जाती है। यह विशा वर्तमान कि केटरी को जरूर समझनी चाहिए।

ऐन वक्त के फैसले की अफरा-तफरी

एच श्रीनिवासन

पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया, तो राजधानी से करीब 2600 किलोमीटर दूर बसे छोटे से शहर शिवकाशी पर इस फैसले का सीधा असर हुआ। पटाखे, मांसि की तीली और कामज के पोंस्टर बनाने के कारोबार का पर्याय बन चुका शिवकाशी ऐसे तख्त रह गया। जिस पर सस्ते उपकरणों ने पहले ही उसकी कमर तोड़ डाली थी, फिर पिछले साल की नौबत आई, और इस साल जीएसटी ने इसे जोरदार झटका दिया। जीएसटी में इसे सर्वाधिक 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में रखा गया है। यह शहर एनसीआर में पटाखा बिक्री पर रोक के लिए तैयार ही नहीं था, जहां पर इसकी कुल बिक्री का करीब 20 फीसदी भाग जाता रहा है।

इस दिवाली में शिवकाशी 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाने जा रहा है। कई सारे कामगारों, खानकम बुजुर्गों के आगे नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगा है। कुछ पटाखा निर्माता बहादुरों के साथ पर्यावरण के अनुकूल पटाखे (ग्रीन फ़ायर) बनाने के दावे कर रहे हैं, तो वहीं इस कारोबार से जुड़े दूसरे तमाम कारोबारी किसी ऐसे रास्ते की तलाश में हैं, जिससे उन्हें अपना कारोबार जारी रखने में मदद मिल सके। कुल मिलाकर, पटाखा उद्योग में एक अफरा-तफरी का माहौल है, लेकिन साथ ही यह हवासस भी है कि उन्हें अपने इस व्यवसाय को नया रूप देने की जरूरत है। पटाखे खेती वाली कंपनियों के मुताबिक, यह क्षेत्र तीन लाख प्रत्यक्ष और 10 लाख परोक्ष रोजगार सृष्टि करता है। इससे छिटपुट प फैकटिंग उद्योग को भी मुनाफा होता है। इसके अलावा, देश भर के लाखों श्रोक व बुद्धर नंदनदरों की आजीविका इस पर आधारित रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका के जरिए पटाखा कारोबारियों के पक्ष में यह दलील भी पेश की थी कि पटाखों के अलावा घृत, गांधिया से निकलने वाले धुआं, इमारतों की निर्माण गतिविधियों और पहाड़ी सूखी में किसानों द्वारा पारसी जलाने से भी एनसीआर में पटाखे प्रदूषण होता है।

इस पूरी बहस को कुछ लोगों ने यह कहते हुए सांप्रदायिक मोड़ देने की कोशिश की कि सरकार को जानवरों की कुर्बानी समेत उन तमाम परंपराओं पर भी गौर करना चाहिए, जिनके कारण प्रदूषण बढ़ता है। कुछ लोगों ने तो कोर्ट द्वारा

पटाखों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को 'हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने' तक ठहरा डाला। कुछ दलील निरुद्ध अतिवाद की हद तक गई, मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली मखान वायु प्रदूषण से जुड़ा रही है। इस महानगर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसकी हवा सदी की शुरुआत में ही प्रदूषण की गिरफ्त में फंस जाती है, और स्मॉग के कारण प्रदूषक तत्व इसमें लंबे समय तक छप रहते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानों से इसकी नजदीकी समस्या को और बढ़ाती है, तो पड़ोसी प्रांतों हरियाणा व पंजाब तरफ से इसकी ओर बहने वाली हवा अपने साथ पराली के जलने से पैदा प्रदूषक तत्व भी लाती है। दिल्ली में



वाहनों की संख्या तो काफी है ही, रात में इससे गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय ट्रक भी यहां के वायु प्रदूषण को और गहरा देते हैं। जलिल है, इस महानगर के बचे और बूढ़े इनसे बुरी तरह भी पेश की गई थी। आखिर जब समाजिक के लिए प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम के लिए टुकड़ों में फैसले करने या उसकी उपेक्षा करने की बजाय एक समग्र नीति की दरकार है, जिस पर लंबे तक तर्क अमल सुनिश्चित कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट का एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध का फैसला दिवाली से महज 10 दिन पहले आया, जबकि ज्यादातर स्टॉक बाजार में आ चुका था। आखिरी वक्त में रात के फैसले से तो कारोबारजोरों की

'माइक्रोमैग्नैट मीटर' यानी एम्पीसीएम होना चाहिए। अजरा जरा दिखने में पीएम 2.5 का स्तर क्या है, इस पर गौर कीजिए। पिछले साल दिवाली की रात दिल्ली के आनंद विहार में पीएम 2.5 का स्तर 883 एम्पीसीएम था, जबकि शहर के कुछ इलाकों में तो यह स्तर 1000 एम्पीसीएम तक पहुंच गया था! इस सोमवार को एनसीओ साख के मुताबिक, पीएम 2.5 का स्तर दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में 303 एम्पीसीएम था। ज्यादातर दिल्लीवाले एन दिखने वाले गैस वेयर में ही रहे हैं। ऐसे में, हमारी की बात नहीं कि दिल्ली दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में एक है। और यह कहने की जरूरत नहीं कि साफ हवा में सांस लेने की

आजादी भी एक नागरिक का बुनियादी अधिकार है। छि दिवाली की रात का ध्वनि प्रदूषण न सिर्फ इंसानों को, बल्कि पशु-पक्षियों को भी बुरी तरह तनावग्रस्त करती है। प्रदूषण की यह समस्या कोई आज अवाक नही खड़ी हुई है। आखिर सरकार क्यों आंखें मूंद रही? शिवकाशी के पटाखा कारोबारों के वर व राज्य सरकारों, औद्योगिक संगठनों और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों से यह कहते रहे कि उन्हें पर्यावरण के दृष्टिकोण पटाखे बनाने की तकनीकी मुद्दा कोई जाए, मगर उन्हें कहां से कोई सुझाव या हल नहीं मिलत। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम के लिए टुकड़ों में फैसले करने या उसकी उपेक्षा करने की बजाय एक समग्र नीति की दरकार है, जिस पर लंबे तक तर्क अमल सुनिश्चित कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट का एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध का फैसला दिवाली से महज 10 दिन पहले आया, जबकि ज्यादातर स्टॉक बाजार में आ चुका था। आखिरी वक्त में रात के फैसले से तो कारोबारजोरों की बांधें खिलेंगी। दिवाली तो अब भी बायु और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली छे अरु है, क्योंकि पटाखे छेनेने पर प्रतिबंध नहीं लगा है। साल 2015 में दिल्ली से माहों के लिए लागू ऑई-इमन योद्धा भी अंतिम क्षणों के समाजिक के लिए प्रदूषण न करने वाली को भी फैसल की आसका बंद गई है, क्योंकि उनके फैसड़े दूधित हवाओं से भर रहे हैं। प्रदूषण के स्तर को बताने के लिए अधिकारी लगातार आंकड़ों का एलान करते हैं। किसी भी इलाके की हवा की गुणवत्ता को पार्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5) के जरिए मापा जाता है। इसमें 2.5 का अंक प्रदूषक कण का आकार है। भारत सरकार के मुताबिक, पीएम 2.5 का घनत्व 40 से 60

केरल में पहल

देवताओं को भक्तों से जोड़ते दलित



आवेदन पत्रों की छंटनी में 36 गैर-ब्राह्मणों को देवालयों के महान्त का दायित्व निभाने के योग्य पाया। इस महत्वपूर्ण नियम का खास पल्लू इस पर के लिए दलितों के यमन की शुरुआत है। नाइसाफी और दमन के सिलसिले को तोड़ते हुए बोर्ड ने एक दलितों को पुजारी की पदवि भूमिका सौंपने का फैसला लिया। कुम्भकर्ण बताने हैं-“मैंने इसके लिए दस साल तक दीक्षा ली। इस दौरान भी सवर्णों की हिकारत को सहता रहा। मेरी साधना घर लाई और आज मुझे मंजिल मिल पाई है।” केरल के पुन्नालूर में ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध संशोधों से बौद्ध समुदाय निरंतर संघर्ष करते रहे। यह लड़ाई रोज तो लगी थी। पूरी तरह साक्षर इस राज्य में अन्य समुदायों को मंदिर का महन्त बनाने की

शुरुआत यूं तो भी कुछ वर्ष पहले कर दी गई थी, लेकिन वे निर्णय जातीय आधार पर नहीं लिए गए थे। इस तथ्य को देखते हुए सरकार ने मांग की गई कि वह पुजारीयों को वेतन राश्व की ओर से मिलता है तो अन्य क्षेत्रों की तरह ही प्रत्याशियों का चयन करते समय आरक्षण के नियम का भी पालन किया जाना चाहिए। इसी तर्क को आधार बनाकर अब जाति आधारित चयनप्रद्धि को अपनाना गया है। यह काम सरकार द्वारा नियंत्रित चयन बोर्ड करता है। यह राज्य के 1248 मंदिरों के पुजारी बनने के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगता है और प्रशिक्षण तथा योग्यता को ध्यान में रखकर उनके नाम चुनता है। आज समाजिक न्याय का संकल्प जित्त मुद्दाम तक पहुंचने में कामयाब हुआ है, यह बहुत लम्बे संघर्ष का

प्रतिफल है। पुजारी का काम संभालना तो दूर, परम्परा के नाम पर छोटी जातियों के लिए पुजारीयत्न में घुसने पर सख्त पाबंदी रही है। इसके खिलाफ संगठित आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के शुरू से ही हो गई थी। 19वीं सदी के तीसरे और चौथे दशक में कांथस के नेतृत्व में हरिजन और दलितों के प्रति इस प्रकार के विरोध में अग्रसार और पदचढ़ाव की गई। 1924 का आंदोलन वायव्य और 1931-32 का संघर्ष इतिहास में गुरुवार सत्याग्रह के नाम से दर्ज है। यहां बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुद्दम को न फेंकल अभी आगे ले जाना होगा वरना और पुख्ता बनाना होगा। लेकिन यह तरी हांगा, जब उन आस्थावानी से सहयोग लिया जा सके, जो मुन्धता से विलत करने वाले अधविश्वासी और कट्टरता के पक्षधर रहे हैं। इस राह में नई बूनीयतों का सामना करने की जरूरत पड़ेगी। जब दलित या गैर-ब्राह्मण स्वामीमाला जैसे बड़े मंदिरों में महंत का आसन स्थापित, उस समय जातीय अंधकार निर्मिताकार होके विधेय के साथ ऐसे फेरालों का मुकामला करेगा। इसीलिए समाजिक सहयोग और स्वीकृति बहुत जरूरी है अन्यथा मेधाव्यवर्जित मेमर्या अंध ही अंध समझ में नई तरह के उद्वारण को जन्म देगा, जो किसी भी दृष्टि से किसी भी धर्म के हित में नहीं होगा। यदि आस्थावानी का सहयोग और मजूरी के साथ आगे के मुकाम हासिल किए गए तो ऐसी कुर्तित से हमेशा के लिए इच्छावर्जित मिल चुकता है, जो छोटे-बड़े हर वर्ग और हर जाति के चहुमुड़ी विचारण, उद्वारण और समान की दिशा में सकारात्मक संघर्ष करेगा। ऐसा होने पर ही सच्ची एक समान अवसर का मौका मिलेगा। सभी समरसता का बोध भी हो सकेगा।

रैगिंग

संवाद और सामंजस्य बनाएं

के बाद भी यह एकदम अती तक अप्रभावी सिद्ध हुआ है, और रैगिंग का चर्च निरंतर जारी है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय 'रैगिंग' पर सख्त रोक लगाने और शिक्षा संस्थाओं को इन घटनाओं में अनिवार्य



जारी किए। कई वर्षों में भी इस पर रोक लगाने के लिए काफी भी कानून। वास्तव में कोलेज में प्रवेश के बाद सीनियर्स का मादौदरन सकारात्मक होना है। विविधावस्था अनुदान-अयोगी (जीएसटी) एक्ट, 1956 में सभी संस्थानों में रैगिंग-विरोधी नीति अपनाना अनिवार्य बनाया गया था। किंतु इतने वर्ष बीत जाने

स्तर के शिक्षा संस्थान ज्यादा हैं, जहां पर दूरदराज के विद्यार्थी अध्ययनरत होते हैं यूनूसीयों के आंकड़ों के अनुसार साल 2009 से 2015 तक उत्तर प्रदेश में 565, पश्चिम बंगाल में 375, पंजाब प्रदेश में 313,

आंध्र प्रदेश में 289 और महाराष्ट्र में 170 रैगिंग के मामलों सामने आए। लेकिन ये आंकड़े पूरी तरह से अचूक नहीं हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश भर के कॉलेजों में करीब 40 फीसद छात्र-छात्राओं को रैगिंग का देश डेलना पड़ता है। लेकिन उनमें से सिर्फ 8.6 फीसद

घटनाएं दर्ज की जाती हैं। ज्यादातर नये छात्रों के साथ रैगिंग की वारदात होती है। ऐसे माहौल में तकरबिन 25 फीसद छात्र पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते जबकि 65 फीसद छात्र पढ़ाई का आनंदभोग हर हारों के कारण खल हो जाते हैं रैगिंग को लेकर यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार शिक्षा संस्थानों

में-रैगिंग विरोधी समितियों के गठन की जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की है। साथ ही, ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कॉलेज-हॉस्टल में रैगिंग विरोधी दस्ती की अवाक छोरमों, कॉलेज केमपास में रैगिंग रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना और शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा के दौरान खाना-खास जगहों पर सज्जों की मौजूदगी की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उन्ना जा रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की बढ़ती हितात्मक प्रवृत्ति शांति और विकास के तमाम पल्लुमानों को धराशायी करते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को भी सकारात्मक रूप से नष्ट करेगा। रैगिंग रोकने के तमाम उपायों के अक्षरदंड इसके न रुकने का कारण इंग्रगुण्य निरंतर संघर्ष करेगा है। ऐसी घटनाओं के लिए सिर्फ छात्रों को जिम्मेदार ठहराना समस्या का हल नहीं है। शिक्षण संस्थानों में नैतिक शिक्षा का अभाव, उपभोक्तावादी जीवन और असंतुलित विकास जलनला बनता जा रहा है। ऐसी रैगिंग कमिटी द्वारा युवकों पर कार्रवाई करने से समस्या रुकने नहीं है, बल्कि विद्यार्थी-शिक्षक संवाद और उन्ने सामंजस्य स्थापित किए जाने के प्रयास सही दिशा। बचो को घर से ही नैतिक शिक्षा दी जाए। उच्च अनुसंधान का पाठ पढ़ना चाहिए। अफसोस कि ऐसे सकारात्मक प्रयास और विद्यार्थियों के चरानात्मक विचार करने में हमारी शैक्षणिक संस्थाएं बुरी तरह फिलत रही हैं।

कौड़ियों के भाव चीनी मिल बेचने वालों को नहीं बख्खेंगे: सीएम

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान चीनी मिलों की बिक्री पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कौड़ियों के भाव से सौदे करने वाले बख्खे नहीं जायेंगे। पिंपपलच की नई चीनी मिल में को-नैशनल एंटर और आसानी के शिलान्यास के मौके पर विशेषियों पर अक्रांति हुर्रे योगी ने कहा, 'प्रदेश को नोचने वालों को जना कभी माफ़ न करे।' उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को लूटा। जमकर घोटाले किए गये। अब इन उपक्रमों को एक साल तक से ज्यादा के लिए 10 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चपा-बसपा की सरकारों ने 21 चीनी मिलों को ऑन-पीन दामों में बेच दिया। चीनी मिलें बंद हुई तो किसान-जीवनान तबाही



की ओर बढ़ने लगे। गेजगार सुजन के बड़े अवसर बंद हो गए। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों को बेचने वाले किसान और विकास के दुश्मन हैं। भाजपा सरकार प्रदेश में नई चीनी मिले लगाने के साथ ही पुनर्गठित की जा विस्तार करेगी। **भोगवादी राजनीति ने जनता को तबाह किया** जनसभा में योगी ने कहा कि राजनीति में जब मूर्ख और आदर्श नहीं रहते हैं तो सत्ता भोग को वस्तु मात्र बन जाती है। भाई भूतोजाद, परिवारवाद और जातिवाद का

बनाया। लेकिन सच्चाई यह है कि ये परिवार के मोह से उदरही नहीं जाए। सत्ता ने यह बताया कि एक परिवार के पास ही सभी पद होंगे, वहीं परिवार सब संचालित करेगा। बसपा ने इस परिवारवाद को व्यक्तित्व में बदलकर और संकुचित कर दिया। **निवेश के लिए अर्द्धकुल महील बनायेंगे** मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग लगे। नीजवातों की अधिकाधिक गेजगार और नौकरों मिले, इसके लिए वह प्रयास कर रहे हैं। ताकि नीजवातों को ज्यादा से ७ यादा गेजगार प्रदान कर सकें। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में अपनी से बंद खाद कारखाने के शिलान्यास से की। प्रदेश सरकार नई उद्योग नीति लेकर आई। कानून का राज स्थापित किया।

अयोध्या में राम मूर्ति के लिए शिंया वक्फ बोर्ड देगा दस चांदी के तीर

इलाहाबाद। लोक सेवा आयोग की पीसीएस भर्ती परीक्षा में इंटरन्यू के अंक को आधा कर दिया गया है। अब इंटरन्यू 200 के बजाय 100 अंकों का होगा। आयोग की बैठक में यह फैसला लिया गया। यह व्यवस्था पीसीएस 2018 परीक्षा से प्रभावी होगी। 2018 की परीक्षा से पीसीएस की मुख्य परीक्षा का पैटर्न बदलकर आईएएस मेंस की तरह कर दिया जाएगा। आयोग के सचिव जगदीश ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंटरन्यू के अंकों को आधा करने का निर्णय चयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया गया है। इंटरन्यू के अंक कम होने से चयन में लिखित परीक्षा के अंकों का महत्व बढ़ जाएगा। इंटरन्यू में अधिक नंबर देकर चयन करने का जो आरोप लगाया था, उससे भी बचा जा सकेगा। गजस्थान और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में इंटरन्यू 100 नंबर का ही होता है। यहां तक यूपी

100 नंबर का होगा पीसीएस का इंटरन्यू, अगले साल से लागू होगी व्यवस्था

लोक सेवा आयोग की पीसीएस जे परीक्षा में भी इंटरन्यू 100 नंबर का ही है। सचिव ने बताया कि नियमावली में व्यवस्था है कि इंटरन्यू का अंक लिखित परीक्षा का अधिकतम 12.2 प्रतिशत तक हो सकता है। यूपी लोक सेवा आयोग में अधिकतम प्रतिशत के अंक को ही लागू कर दिया गया था। पिछले दिनों हुई आयोग की बैठक में इन सारे पहलुओं पर विचार कर भर्तियों से इंटरन्यू को समाप्त करने की प्रेरणा सरकार की संस्था को देखाते हुए इंटरन्यू के अंक कम करने का निर्णय चयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया गया है। इंटरन्यू के अंक कम होने से चयन में लिखित परीक्षा के अंकों का महत्व बढ़ जाएगा। इंटरन्यू में अधिक नंबर देकर चयन करने का जो आरोप लगाया था, उससे भी बचा जा सकेगा। गजस्थान और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में इंटरन्यू 100 नंबर का ही होता है। यहां तक यूपी

पूर्व में पीसीएस मेंस का नया पाठ्यक्रम तैयार किया था। इसकी संस्था कराई जाएगी फिर इसे मंजूरी के लिए साशन को भेजा जाएगा। पिछले दिनों मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बदलाव पर शासन की सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। आईएसएस और पीसीएस मेंस के पाठ्यक्रम में काफी अंतर है। आईएसएस मेंस में निबंध और अंग्रेजी का 300 नंबर का पेपर होता है। 250-250 नंबर के सामान्य अध्ययन (जीएस) के चार पेपर होते हैं। वैकल्पिक विषय दो के बजाए एक कर दिया गया है। इस एक विषय के दो पेपर 250-250 नंबर के होते हैं। इस प्रकार कुल 1800 नंबर की लिखित परीक्षा और 275 नंबर का इंटरन्यू होता है। वहीं पीसीएस मेंस में अभी भी दो वैकल्पिक विषय हैं। इसके दो-दो यानी कुल चार पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होगा।

यूपी-उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा जल्द, यूपी के डिट्टी सीएम ने बताया भरोसा

देहरादून। यूपी के डिट्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तराखंड के दो दिवसीय दौर पर हैं। सोमवार दोपहर वे यूपी निर्माण निगम के वरिष्ठ इंजीनियरों के साथ देहरादून पहुंचे। उचित विश्राम उन्होंने बीबापुर गेजट हाउस में किया। वहीं से सुबह केदारनाथ के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड व यूपी के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा जल्द होगा। पश्चिमोत्तर नरेंद्र मोदी की अनुग्रहता में दोनों प्रदेशों का विकास तेजी से होगा। बीते सोमवार को मौर्य न्यू कैट रोड स्थित मुख्यमंत्री त्रिवेद रावत

से मिले। दोनों नेताओं के बीच अनुरोध मूढ़ी पर लंबी मंशा हुई। पत्रकारों से बातचीत में मौर्य ने कहा कि मोदी विकास के मामले में आदर्श हैं। जनता ने यूपी और उत्तराखंड को जो प्रबंध बख्शा दिए, निश्चित ही दोनों प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों प्रदेश भाई की तरह परिसंपत्तियों के लंबित मामलों के निराकरण को उदात्त पूर्वक काम करेंगे। सीएम त्रिवेद ने कहा कुछ मसलों पर सहमति बन चुकी है। अगले साह से लखनऊ जा रहे हैं और लंबित मामलों का चर्चा करेंगे।

योगी सरकार का कदम: ऑनलाइन जानकारी न देने वाले 2682 मदरसी की मान्यता हो सकती है रद्द लायका। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से जुड़े 2682 मदरसों द्वारा तय समय सीमा के भीतर उप सरकार को ऑनलाइन जानकारी नहीं देने के कारण इन मदरसों की मान्यता रद्द की जाएगी। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन विवरण अपलोड करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर थी। वहीं, जब 15 अक्टूबर को विवरण अपलोड करने वाले 16461 मदरसों की मान्यता वाकफ़ रहेगी और उन्हें अनुदान का हक होगा।

मैनपुरी में खेत में सोते किसान की हत्या

आगरा। पंचनाथ क्षेत्र के ग्राम कांसेपुर में फसल की रखवाली करने गए किसान की धातुर हथियारों से हत्या कर दी गई। मंगलवार को तड़के उसका शव खेत पर पड़ा मिला। जानकारी होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। मौके पर फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीमें लेकर पुलिस पहुंच गई। पंचनाथ पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ग्राम कांसेपुर निवासी 45 वर्षीय सर्वेश यादव पुत्र देवराज यादव खेती किसानों के अलगाव कथावाचक का काम भी करते हैं। सोमवार की रात ७ बजे के करीब वो अपने घर से मरक की फसल की रखवाली करने के लिए निकल



गया। रात में किसी समय धातुर हथियारों से उसके गिर और गंदन पर बार कर हत्या कर दी गई। सुबह होते ही उसकी पत्नी गीता देवी रोज की तरह खेतों पर पहुंची तो चारपाई पर सर्वेश का शव देखकर चौंख पड़ी। शोरगुल होने पर पूरे गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। जानकारी पाकर सीओ भोगांव प्रसादों पांडेय पुलिस को लेकर मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीमों ने भी घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाए। **बंदखोर के विवाद में हत्या होने की बात असंगत है सामने** मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजन और ग्रामीणों से घटना की

जानकारी लेकर शव को पंचनाथ पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक एक वृद्ध तथा दो पुत्रियां का पिता था। उसकी हत्या के पीछे कोई दोस कारण सामने नहीं आ सका है। हालांकि परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक काफी समय से मृगक का बंटवारा को लेकर अपने परिवारों से विवाद चल रहा था। बंटवारे के विवाद में ही हत्या होने की बात पुलिस कह रही है। घटना की तत्पश्चात् मृगक की पत्नी की ओर से नामजदी के खिलाफ दो ईआई है। एसपी गजेश का का कहना है कि हथौरे के आधार पर घटना का अभिप्राय दर्ज करवा गया है। हथौरे की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।

लव मैरिज के बाद दूसरे से प्यार करने लगी पत्नी, कार में मिला पति का शव

गया,बिहार के गया में एक युवक की मर्त में गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम दीपक कुमार है। दीपक के घरवालों ने हत्या के लिए अपनी ही बहू को जिम्मेदार बताया है। परिवारों का आरोप है कि दीपक की पत्नी प्रियंका ने ही अवैध संबंध के चलते उसकी हत्या कर दी। चार साल पहले किया था लव मैरिज... घटना गया जिला के रामपुर थाना क्षेत्र के शालीनगर की है। मंगलवार सुबह घर के सामने पार्क कार से दीपक का शव मिला। परिवारों के अनुसार दीपक और प्रियंका ने चार साल पहले लव मैरिज की थी। करीब तीन साल तक दोनों का रिश्ता ठीक रहा बाद में दोनों के बीच विवाद होने लगा। इस दौरान प्रियंका को किसी और से प्यार हो गया। वह पति और समसुलत के लोगों से छिपकर अपने पति से मिलती थी। दीपक को जब इस प्रेम कहानी



के बारे में पता चला तो उसने पत्नी को प्रेमी से मिलने से रोका। प्रेमी से मिलने पर रोके दीपक के चलते प्रियंका अपने पति के जान की दुश्मन बन गई। कुछ दिन पहले ही रात में सोते वक दीपक की हत्या की कोशिश की गई थी। इसी दौरान दीपक की नींद खुल गई थी, जिससे वह बच गया था। दीपक के भाई ने कहा कि प्रियंका को पता था कि हमला किसने किया है, लेकिन वह बात नहीं रही है। कोल करके घर से बाहर बुलाया,

बिहार राबड़ी देवी पूछताछ के लिए ईडी नहीं आई



नई दिल्ली। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एक बार फिर पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नहीं पहुंची। ईडी ने उन्हें रेलवे होटल रखवाला सौदे में कथित घोटाले की पूछताछ के लिए तलब किया था। ईडी उन्हें जल्द नया समन जारी कर सकता है। पर साथ ही ईडी राबड़ी देवी के खिलाफ दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ कर चुकी है। रेलवे होटल रखवाला आवंटन घोटाले के मामले में सीबीआई भी गजद सुप्रियो लाल यादव से पूछताछ कर चुकी है। ईडी एक अधिकारी ने कहा कि जल्द ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए समन जारी किए जाएंगे। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने पूछताछ के लिए दोहराया पैरा होने से पहले आठ साह का वक मांगा है। पर ईडी राबड़ी देवी से पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव को जल्द पूछताछ के लिए बुला सकता है।

गया-पटना पैसेंजर ट्रेन में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग



पटना। ट्रेन नंबर 63244, गया-पटना मेमू पैसेंजर ट्रेन में शॉर्ट सर्किट से मंगलवार सुबह आग लग गई। आग की खबर लगते ही ट्रेन को गया से आगे चाकन्द स्टेशन पर रोका गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल रेलवे नोटेस की टीम को उसे ठीक करने में लगाया गया। मंगलवार सुबह ट्रेन गया से चलकर पटना जा रही थी कि तभी गया से आगे चाकन्द स्टेशन पर लोगों को ट्रेन से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। इसकी जानकारी तुरंत रेलवे को दी गई। वहां मौजूद यात्रियों ने ट्रेन के नीचे से निकल रहे धुएं की जानकारी गाई और ड्राइवर को दी। ट्रेन में हुई शॉर्ट सर्किट की वजह से वायरिंग डैमेज हो गया था। इस वजह से मोटर काम नहीं कर रहा था, जिससे ट्रेन के अंदर लाइट और पंखा भी नहीं चल रहा था। करीब आधे घंटे से ज्यादा वक



तक ट्रेन को रेंके खने के बाद उसे ठीक कर फिर से पटना के लिए रवाना कर दिया गया। इसके बाद ट्रेन को चाकन्द से आगे नियामनपुर हाँटर पर फिर से रोक दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ट्रेन का चक्का जाम होने की वजह से इसे फिर से रोका गया। ड्राइवर का कहना है कि चक्का पूरी तरह जाम हो गया है। वह ट्रेक को डैमेज कर सकता

तांत्रिक ने अपने रिश्तेदार और बच्ची पर फेंका तेजाब

सहसा, बिहार के सहसा जिले के बिहार थाना क्षेत्र के पटोरी गांव में सोमवार को रात एक तांत्रिक अपने साली के घर गया। उसने साली के हसबैंड और तेजाब फेंककर दिया। तेजाब फेंकने के बाद भी बाद भी वह घर में डटा रहा। परिवारों ने दोनों को पीपलसी में भर्ती करवाया। फिर डॉक्टरों ने सरर हॉस्पिटल रेफर कर दिया। साली के पति पर लगाया अवैध संबंध का आरोप...



घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी सैनी महतो ने अपने साहू भूलन महतो के घर पहुंच कर एक खुले लोई अंदर धारा और भूलन और उसकी बेटी सुप्रसन्न पर तेजाब फेंक दिया। घटना की जानकारी मिलते ही घर के लोग जुटे और दोनों को हॉस्पिटल ले गए।

दरदनाक: सफाई में लगे थे घरवाले, बाल्टी में डूब मरा बच्चा

मोवा (समस्तीपुर)। हवाई ओपी की सारंगपुर पश्चिमी पंचसत के वार्ड संख्या-9 निवासी महेंद्र सहनी के पोता व प्रमोद सहनी के पुत्र शिवम (18 महने) की पानी से भरे बाल्टी में डूबने से मौत हो गयी। वह घटना सोमवार सुबह उस समय हुई जब घर वाले दीपावली के लिए घर की सफाई में जुटे थे। खेलते-खेलते शिवम कच पानी से भरे बाल्टी में गिर गया पता ही नहीं चला। हालांकि घर वालों ने पथ की तेज आवाज सुनी थी। काफी देर के बाद जब बच्चे की आवाज नहीं सुन घर वाले उसे ढूँढने लगे तो वह बाल्टी में अंभी मुड़े हुए पड़ा था। अग्रमान लगाया जा रहा है कि पहले लव बाटोटी पकड़ कर खड़ा हुआ होगा फिर उसी क्रम



में वह सिर के बल बाल्टी में गिर गया होगा। हालांकि बाल्टी में उसके गिरने पर आवाज भी हुई, पर सफाई में जुटे घर वालों ने समझा कि बच्चा खेल रहा है। इस घटना से घर के लोगों में 'चौख

एंबुलेंस न मिलने पर बोलेरो की छत पर बांध कर ले गए शव

मधुबनी। सदर अस्पताल से सोमवार को सड़क हादसे में मारे गए वृद्ध के शव को बोलेरो पर बांधकर ले जाया गया। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। एक तरफ जहां मृतक के परिवारों का कथित आरोप है कि उन्हें शव वाहन नहीं मिला, तो दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन ने कहा कि परिवारों की ओर से शव वाहन की पड़ोनों नहीं की गई। इसकी तस्वीर मीडिया सहित अन्य गुं रसों पर भी वायरल कर दी गई। फुलपरास थाना क्षेत्र के सिमोलीन निवासी 65 वर्षीय नवेन्द्र झा की मौत सड़क दुर्घटना में रविवार को हुई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने सदर अस्पताल लाया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवारों को सौंपा गया। जब परिवारों ने शव वाहन की कमी देखी तो उन्होंने कहा कि हथौरे के आधार पर घटना का अभिप्राय दर्ज करवा गया है। हथौरे की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।

